दृष्टि The Vision

सामान्य अध्ययन (टेस्ट - XVI)

GENERAL STUDIES (Test - XVI)

मॉड्यूल - XVI / Module - XVI

DTVF/18(JS)–M–**GS16**

निर्धारित समयः तीन घंटे *Time allowed: Three Hours*	*अधिकतम अंकः 250* *Maximum Marks: 250*

नाम (Name): Ravi Kumar Sihag

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? हाँ ✓ नहीं

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date): 16 16/07/18

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2018] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2018]:

1	1	3	9	4	7	9

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): हिन्दी

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature):

नोटः प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis

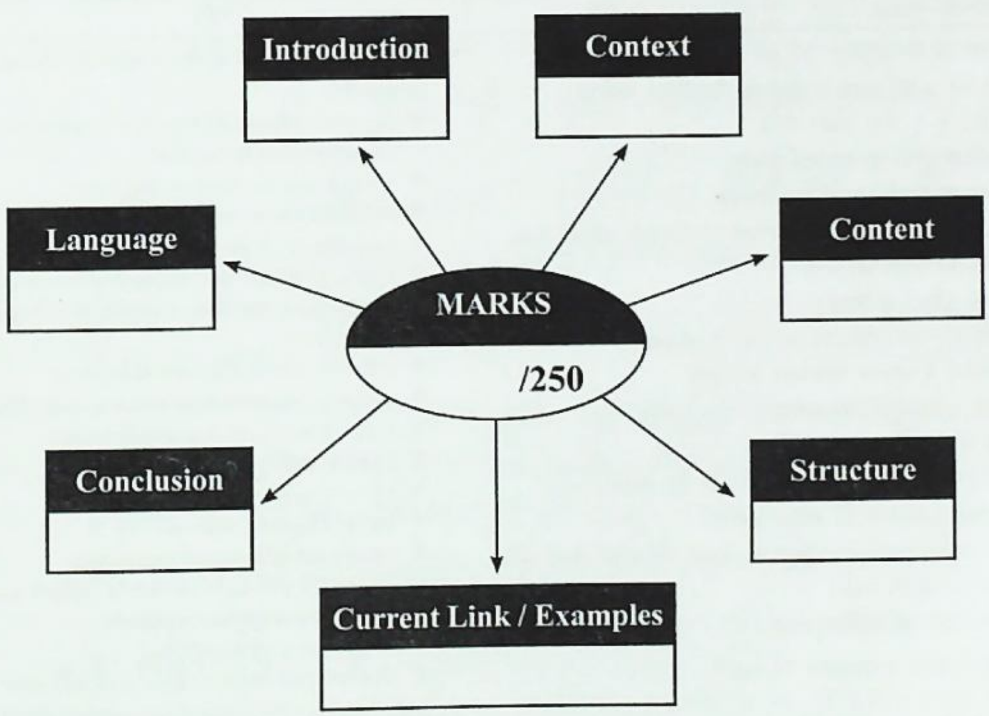

मूल्यांकनकर्त्ता (कोड तथा हस्ताक्षर)
Evaluator (Code & Signatures)

पुनरीक्षणकर्त्ता (कोड तथा हस्ताक्षर)
Reviewer (Code & Signatures)

दृष्टि The Vision

मूल्यांकन की पद्धति

प्रिय अभ्यर्थियों,

आपकी उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए परीक्षक-समूह के सदस्य निम्नलिखित निर्देशों का ध्यान रखते हैं। आप भी इन्हें ध्यान से पढ़ें ताकि आप अपने प्राप्तांकों का तार्किक कारण समझ सकें।

परीक्षकों के लिये निर्देश

1. मूल्यांकन में अंकों का वही स्तर रखा जाना चाहिये जैसा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के परीक्षकों द्वारा रखा जाता है।
2. सामान्य अध्ययन का जो उत्तर हर दृष्टिकोण से सटीक व उत्कृष्ट है; उसे अधिकतम 60% अंक दिये जाने चाहियें क्योंकि आयोग द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन में भी इससे अधिक अंक मिलना लगभग असंभव है। वैकल्पिक विषयों के उत्कृष्ट उत्तरों तथा श्रेष्ठतम निबंधों में अधिकतम 70% तक अंक दिये जा सकते हैं।
3. कृपया अंकों का वितरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार करें-

Method of Evaluation

Dear Candidates,

While assessing your answer-scripts, the evaluators are required to follow the given instructions. You should also read them carefully to understand the logic behind the marks obtained by you in the tests.

Instructions for the Evaluators

1. The level of marks while evaluating the answers should be kept as per UPSC (Union Public Service Commission) standards as far as possible.
2. The answers of General Studies which are accurate and excellent from every perspective should be awarded a maximum of 60% marks as it is almost impossible to get more than that in actual UPSC examination. Excellent answers in optional subjects and the best written essays can be awarded a maximum of 70% marks.
3. Please assign the marks according to the following table-

उत्तर का स्तर (Standard of Answer)	सामान्य अध्ययन में अंक-स्तर (Marks Standard G.S.)	वैकल्पिक विषय तथा निबंध में अंक-स्तर (Marks Standard - Optional Subject and Essay)
उत्कृष्ट (Excellent)	51-60%	61-70%
बहुत अच्छा (Very Good)	41-50%	51-60%
अच्छा (Good)	31-40%	41-50%
औसत (Average)	21-30%	31-40%
कमज़ोर (Poor)	0-20%	0-30%

4. कृपया उत्तर में निम्नलिखित गुणों को विशेष प्रोत्साहन दें-
   - प्रश्न की सटीक समझ व उत्तर की व्यवस्थित रूपरेखा
   - संक्षिप्त, टू-द-पॉइंट लेखन शैली
   - प्रामाणिक तथ्यों का समुचित उपयोग
   - अधिकतम ज़रूरी बिंदुओं का समावेश
   - सरकारी दस्तावेज़ों (मंत्रालयों/आयोगों की रिपोर्ट्स, पॉलिसी पेपर्स आदि) के संदर्भों की चर्चा
   - प्रभावी भूमिका व निष्कर्ष
   - समकालीन घटनाओं/प्रसंगों को उत्तर से जोड़ना
   - दृष्टिकोण में संतुलन, समावेशन व गहराई
   - अच्छी, साफ-सुथरी हैंडराइटिंग
   - भाषा में प्रवाह
   - आवश्यकतानुसार डायग्राम्स, नक्शों आदि का प्रयोग
   - तकनीकी शब्दावली का सटीक उपयोग
   - सुंदर प्रस्तुति शैली (छोटे पैराग्राफ्स रखना, महत्त्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करना आदि)
   - विराम चिह्नों का समुचित प्रयोग
   - भाषा में वर्तनी व व्याकरण की शुद्धता
5. टॉपर्स के अनुभव बताते हैं कि उत्तर की विषयवस्तु अच्छी होने पर आयोग के परीक्षक शब्द-सीमा के थोड़े बहुत उल्लंघन पर अंक नहीं काटते हैं। कृपया आप भी इसी दृष्टिकोण के अनुसार अंक-निर्धारण करें।

4. Please devote special attention to the following qualities in an answer–
   - Accurate understanding of the question and systematic presentation of the answer
   - Crisp and to the point writing style
   - Adequate use of authentic facts
   - Inclusion of all the important points
   - Citing of relevant facts and figures from relevant official documents (Ministries /Commissions Reports, Policy Papers etc.)
   - Effective introduction and conclusion
   - Linking of current events and situations with the answer
   - Balance and depth in answer-writing
   - Legible and clean handwriting
   - Flow of language
   - Use of diagrams, maps etc
   - Precise use of technical terminology
   - Beautiful presentation style (small paragraphs, underlining important words etc.)
   - Proper use of punctuations
   - Correct spellings and right use of grammar
5. Experience of UPSC toppers also indicates that if the content of the answer is good, the UPSC examiners do not cut the marks on slight violations of the word-limit. Please award marks strictly according to the above-mentioned instructions.

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

1. भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव एवं उनकी असुरक्षा से संबंधित विभिन्न कारकों की पहचान करें। साथ ही, सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये किये जाने वाले प्रयासों की चर्चा करते हुए सुधार के संबंध में अपना मत दें। (200 शब्द) 12.5

Identify the various factors related to discrimination and lack of security for women in India. Discuss the steps taken by the government in this regard and suggest measures for improvement. (200 words) 12.5

आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार भारतवर्ष में 63 मिलियन महिलाएँ 'गुमशुदा' हैं और 21 मिलियन बच्चियाँ 'अवांछित' हैं। स्पष्ट है ऐसे भयावह आँकड़े महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव एवं उनकी असुरक्षा से कारण हैं।

विभिन्न कारक

① सामाजिक कारक :-

– परंपरागत रूढ़ीवादी सोच व पितृसत्तात्मकता की प्रवृत्ति जिसके कारण पुरुषों को प्रधानता दी जाती है एवं महिलाओं को 'संतान-जनने' एवं 'पारिवारिक अस्मिता' के कारक के रूप में घरेलू कार्यों तक सीमित कर दिया जाता है।

② धार्मिक :- 'बेटा ही सारे क्रियाकर्मों का वाहक होगा' जैसी सोच बेटियों के पिछड़ेपन का कारक है। साथ ही पुराने धर्मग्रन्थों में भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले निम्न स्थिति दी गई है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

③ आर्थिक स्तर पर :- कार्यस्थलों का पुरुषानुकूल होना।
- महिलाओं का 'पिंक कॉलर' जॉब तक सीमित होना
- 'ग्लास सीलिंग' की संकल्पना कि महिलाएँ अच्छे निर्णय नहीं ले पाती।
- कार्यस्थलों पर महिलाओं का उत्पीडन एवं पुरुषों में संवेदनशीलता का अभाव।

अन्य - राजनीतिक स्तर पर प्रयास न होना।
- लिंग कानूनों का उचित कार्यान्वयन न होना।

सरकारी प्रयास
① महिला अधिकारों के संबंध में :-
(क) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन से सुरक्षा अधिनियम 2013
(ख) ~~सम्बन्ध~~ विशाखा दिशा - निर्देश।
(ग) शी- बॉक्स पोर्टल जैसे नवाचार
(घ) घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
② महिला सशक्तिकरण संबंधी
(क) महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन - हालिया 'महिला शक्ति केन्द्र' योजना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

(ख) 'वन स्टॉप सेंटर' (सुरक्षा हेतु)
(ग) मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम
(घ) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना - जागरूकता प्रसार हेतु।

शिक्षा व स्वास्थ्य स्तर पर :- कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नौकरियों में आरक्षण (अनुच्छेद 15(3)) आदि।

अन्य स्तर जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है -

(क) प्रशासन के स्तर पर संवेदना के सुधार का प्रयास करना चाहिये
(ख) 'जेंडर बजटिंग' को और अधिक विकसित करना चाहिये।
(ग) महिलाओं के विकास हेतु स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को बढ़ाते हुए बांग्लादेश के मोहम्मद युनुस के मॉडल का अनुसरण पर ध्यान देना चाहिये।
(घ) महिला आरक्षण विधेयक (108 वां संशोधन) को पारित करना चाहिये।
(ङ) स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं की भूमिका के विस्तार के प्रयास भी लाभकारी होंगे।
(च) अन्ततः मानसिकता बदलाव के कार्यक्रमों की ओर बढ़ना चाहिये।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

2. बाल विवाह के मामले में भारत अभी भी विश्व के अग्रणी देशों में आता है, क्या इस कुप्रथा का कारण परंपरागत रूढ़िवादी सोच है? तर्क सहित विश्लेषण करें। साथ ही, इस संदर्भ में सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की चर्चा करते हुए इसे रोकने के उपाय भी सुझायें। (200 शब्द) 12.5

India leads the countries in child marriages. Is the prevalent conservative mindset responsible for continuance of this evil practice? Analyse. Discuss the steps taken by the government and suggest measures to deal with it. (200 words) 12.5

हाल ही में यूनेस्को की रिपोर्ट में द० एशिया के क्षेत्र में बालविवाह की कमी का हवाला दिया गया परन्तु 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' के अनुसार 2015-16 में 28.8 % बालिकाओं या बालकों का विवाह 18 वर्ष से पूर्व किया गया है। आँकड़ों के स्तर पर यह एक भयावह स्थिति है।

कारणों के स्तर पर देखें तो अनेक सामाजिक, धार्मिक कारण इस संबंध में उल्लेखनीय हैं जैसे - महिलाओं की सुरक्षा की समस्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण एक साथ बड़े- छोटे का विवाह करना, धार्मिक मान्यताएँ जिसमें कन्या को रजस्वला होने से पहले ही विवाहित कर देना आदि शामिल हैं, परंतु रूढ़ीवादी मानसिकता इसका प्रमुख कारक है जिसके निम्न स्तर दृष्टिगोचर हैं -

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(क) बालिकाओं को जिम्मेदारी समझना जिससे उनका शीघ्र विवाह कर जिम्मेदारीमुक्त होने की मानसिकता।

(ख) दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ ~~का~~

(ग) विवाह पर अधिक खर्च होना, जिसके परिणाम में राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में बड़े-छोटे सभी बालकों का विवाह एक साथ कर दिया जाता है।

(घ) पारंपरिक समाज में महिला असुरक्षा की स्थिति जिसके कारण उसकी असुरक्षा का एकमात्र निदान विवाह माना जाता है

(ङ.) रूढ़ीवादी मान्यताएँ जिनके कारण 'अक्षय तृतीया' पर अनेक बालविवाह होते हैं।

(च) बालिका शिक्षा के प्रति यथास्थितिवादी सोच।

सरकार के प्रयास :-

(क) निरोधक उपाय :-

(क) बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 - जिलाधिकारी को शक्तियाँ प्रदान करता है कि वह बाल-विवाह रोकने के प्रयास करें।

(ख) दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961 - दहेज

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

लेना व देना दण्डनीय अपराध है

② जागरूकता उपाय

उपाय →
- बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु योजना (कस्तूरबा गांधी विद्यालय)
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- जागरूकता अभियान : 'सेल्फी विद डॉटर'
- सशर्त नकद हस्तान्तरण + सुकन्या समृद्धि योजना

रोकने के अन्य उपाय

(क) सिविल समाज, एन.जी.ओ. को सरकार के साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाया जाना चाहिये।

(ख) दहेज व बालविवाह के कानूनों का असरदार पालन होना चाहिये। जिलाधिकारी को ऐसे विवाहों को निरस्त करने व बच्चों के संरक्षण व विकास की जिम्मेदारी देनी चाहिये

एक अन्य उपाय विवाह के खर्च को नियमित करने का अधिनियम लाकर भी किया जा सकता है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

3. क्या मात्र मादक पेय पदार्थों के विक्रय स्थल पर नियंत्रण लगाने से इस समस्या का समाधान संभव है या इस मामले में कुछ अन्य प्रयास किये जाने की आवश्यकता है? विश्लेषण करें। (200 शब्द) 12.5

Can the issue of alcoholism be addressed only by controlling its sale or it requires other measures as well? Analyse. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

मादक पदार्थों के सेवन की समस्या भारत के आर्थिक, सामाजिक विकास में प्रमुख बाधक है। पिछले राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भी शराब के सन्दर्भ में इसी तरह का वर्णन मिलता है। प्रश्न उठता है कि क्या विक्रय स्थल पर नियंत्रण लगाना इस समस्या का उचित समाधान है-

शराब पीना जैसी बुराईयाँ समाज के स्तर पर विद्यमान है। अगर इतिहास में नज़र दौड़ाएँ में सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों को मिटाने के लिये केवल सरकारी प्रयत्न आवश्यक नहीं होते हैं, बल्कि समाज का सहयोग अपेक्षित होता है उदाहरण चाहे बाल विवाह निषेध का हो या दहेज विरोध दोनों अधिनियम सामाजिक असहयोग के कारण ही इतने

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

प्रभावी नहीं है, अतः विक्रय पर प्रतिबंध लगाने से जहाँ शराब सेवन में कमी आयेगी तो तस्करी जैसी नयी समस्याएँ खडी हो सकती हैं। अतः सरकार को चाहिये कि कड़े क्रियान्वयन के साथ निम्न प्रबंधन करें-

(क) अवैध शराब माफिया पर बैन लगाना।

(ख) सामाजिक जागरूकता फैलाना विशेषकर महिलाओं के स्तर पर क्योंकि शराब जैसे तत्वों की मार महिलाओं को सबसे अधिक झेलनी पड़ती है। इसके लिये पंचायतों के स्तर पर प्रयास किया जा सकता है)

(ग) अति वृद्धों के लिये चिकित्सकीय परामर्श से कुछ मात्रा जारी रखी जा सकती है

(घ) करिश्माई व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर जागरूकता प्रसार करना।

(ङ) जो लोग शराब छोड़ चुके हैं, उन्हें उदाहरण के रूप में पेश करना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(घ) पुनर्वास, नशामुक्ति केन्द्रों को खोलना व उनके लिये उचित संसाधनों की व्यवस्था करना

(ङ) शराब की लत छुड़ाने आदि के लिये 2014 में बनाये गये अधिनियम का शब्दशः क्रियान्वयन करना।

अतः उपर्युक्त उपायों के साथ उचित प्रतिबद्धता के साथ यदि शराबबंदी को लागू किया जाये तो ऐसा करना असंभव नहीं है। इसके लिये 'बॉटम अप' या विकेन्द्रीकृत एप्रोच' पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। तभी संविधान के अनुच्छेद 47 के प्रावधानों के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

4. भारत में कुपोषण की समस्या भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास के भविष्य पर आसन्न संकट के समान है। इस संकट के समाधान हेतु 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' एवं 'जीरो हंगर कार्यक्रम' के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु कुछ नवाचारी उपायों की चर्चा करें। (200 शब्द) 12.5

The issue of malnutrition endangers social and economic development of India. In this context, highlight the importance of 'National Nutrition Mission' and 'Zero Hunger Programme'. Also suggest some innovative measures to tackle the issue. (200 words) 12.5

हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय पोषण रणनीति' के उद्घाटन के समय कुपोषण को भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास के भविष्य पर संकट के समान बताया

क्यों?

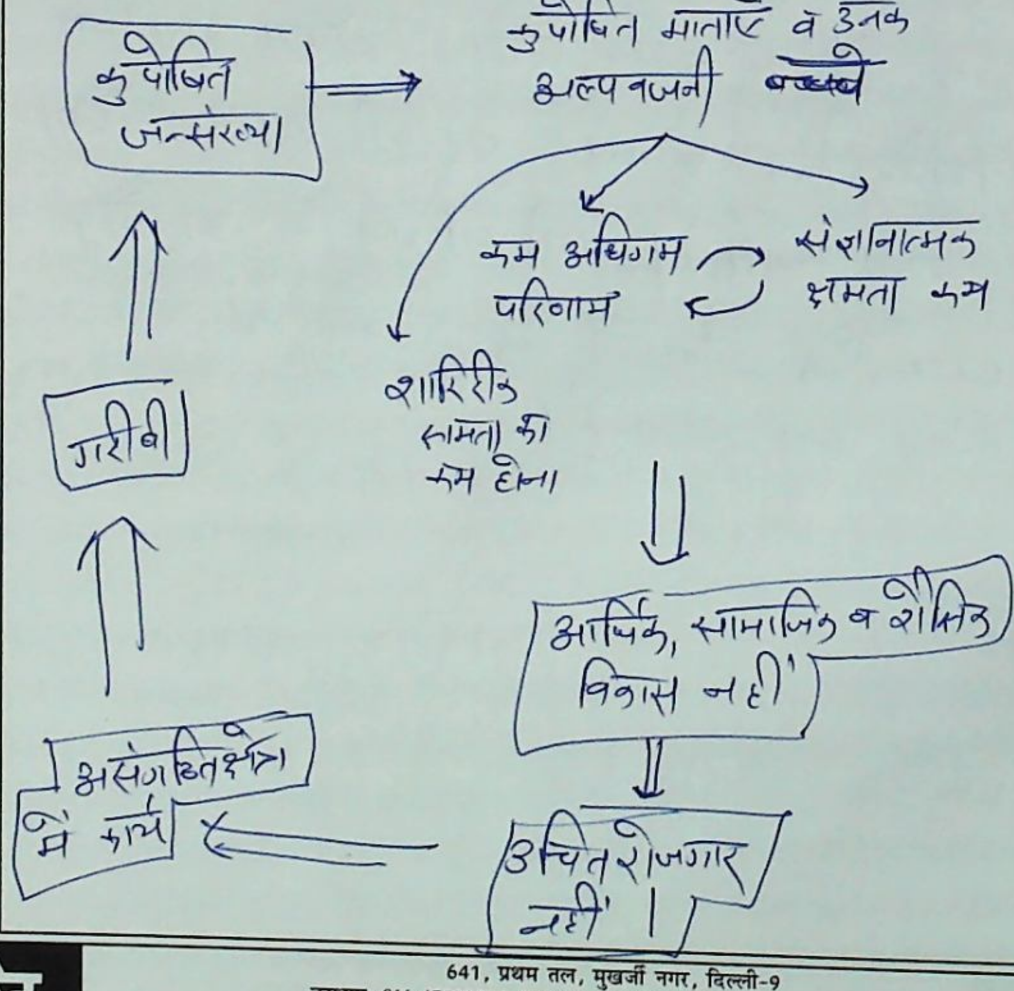

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

राष्ट्रीय पोषण मिशन : 2017-20 तक कुपोषण की समस्या के निदान हेतु युद्धस्तर के प्रयास करना।

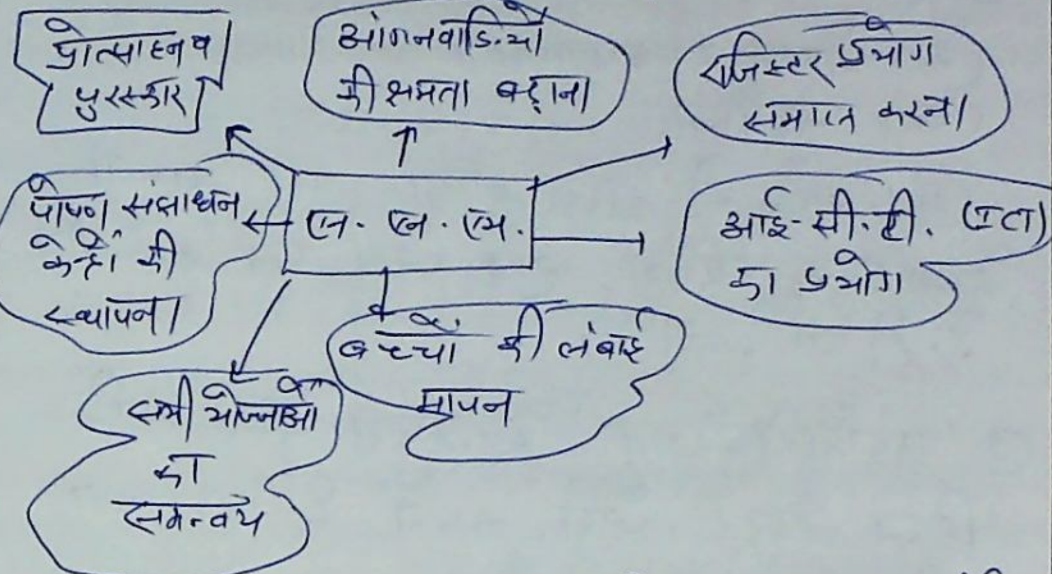

लक्ष्य : अल्पवजन, कुपोषण, ठिगनापन व एनीमिया को क्रमशः 2, 2, 2, व 3 प्रतिशत कम करना 2022 तक

जीरो हंगर कार्यक्रम : यह कार्यक्रम यू.एन.-एफ.ए.ओ के सहयोग से रा० कृषि अनुसंधान परिषद के साथ राज्य सरकारों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है-

"कृषि क्षेत्रों में उचित हस्तक्षेपों द्वारा अनाज व अन्य पोषक तत्वों से युक्त दालों आदि के द्वारा कुपोषण को समाप्त करना"

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

अन्य नवाचारी उपाय :- तीन स्तरों पर सरकार को प्रयास करना चाहिये।

(क) भोजन की उपलब्धता
(ख) वहनीयता
(ग) शरीर की ग्रहण क्षमता - यह क्षमता केवल स्वच्छ परिवेश, शुद्ध जल एवं हाइजीन से ही आ सकती है।

② 'फूड फोर्टिफिकेशन' हेतु प्रयास करना ताकि 'हिडन हंगर' जैसे कारकों से लड़ा जा सके।

③ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में वृद्धि कर भोजन का विविधता बढ़ाना।

④ सरकारी पी.डी. एस प्रणाली को और अधिक सुधार की ज़रूरत है 'आधार, जैम के प्रयोग द्वारा नवाचार पर बल देना।

⑤ सार्वभौमिक बेसिक आय पर भी विचार किया जा सकता है

⑥ मोटे अनाजों की उपलब्धता पर विचार करना चाहिये जो देश के स्थिति के अनुरूप भी है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

5. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षात्मक परिवेश उपलब्ध कराने के लिये लाया गया ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016 कितना उपयोगी साबित होगा? आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (200 शब्द) 12.5

To what extent the Transgender (Protection of Rights) Bill, 2016 will be helpful in serving the interests of transgenders? Critically evaluate. (200 words) 12.5

भारत के सर्वाधिक वंचित, शोषित एवं पिछड़े समुदायों में से एक ट्रांसजेंडर समुदाय भी है। पिछले कुछ समय से इस समुदाय के अधिकारों हेतु कानूनी समाधानों की चर्चा की जा रही थी। इन परिस्थितियों में यह विधेयक उपयोगी साबित हो सकता है।

प्रमुख प्रावधान

(क) ट्रांसजेंडरों की विस्तृत परिभाषा - जो न पुरुष, न महिला हो, जिसकी लैंगिक अभिवृत्ति उसके जन्मागत लिंग से अलग हो व अन्य मानक।

(ख) रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से रोकने पर दंड

(ग) पहचान प्रमाण पत्र हेतु जिलाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं एवं

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

नाबालिग की स्थिति में आवेदन उसके माता पिता करेंगे।

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर एक 'परिषद्' की स्थापना की जायेगी जो कानून के प्रावधानों का क्रियान्वयन देखने के साथ-साथ, सलाहकारी भूमिका का भी निर्वहन करेगी।

(ङ.) उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना व दण्ड जैसी व्यवस्था।

आलोचनाएँ :-

(क) ट्रांसजेंडरों को स्व-पहचान का अधिकार न देना उनकी गरिमा के विरुद्ध है। साथ ही जिलाधिकारी किन मानकों के अनुरूप इन्हें पहचान-पत्र देगा, यह भी इनकी गोपनीयता के विरुद्ध होगा।

(ख) ट्रांसजेंडरों के उत्पीड़न को परिभाषित न किया जाना।

(ग) आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं।

(घ) 'परिषद्' की जगह 'आयोग' की स्थापना

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

की जानी चाहिये थी एवं इसे न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिये थी।

(उ) कुछ आलोचकों के अनुसार उपर्युक्त विधेयक में ट्रांसजेंडरों की परिभाषा भी उचित नहीं है, साथ ही दण्ड के प्रावधान भी कठोर नहीं हैं।

अतः ट्रांसजेंडरों को एक स्वाभाविक अल्पसंख्यक मानते हुए उनके जीवन को गरिमामय एवं शोषण रहित बनाते हुए सरकार को सिविल समाज आदि से सलाह लेते हुए विधेयक में सुधार के प्रयास की करने चाहिये ताकि यह इन समुदायों की रक्षा का प्रभावी उपकरण साबित हो, न कि एक कागजी शेर।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान मे कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

6. 'ग्राम उदय से भारत उदय अभियान' के उद्देश्य क्या हैं? यह ग्रामीण भारत के सशक्तीकरण में कितना कारगर साबित होगा? स्पष्ट कीजिये। (200 शब्द) 12.5

What are the objectives of 'Gram Uday se Bharat Uday Abhiyan'? How far will it be effective in empowering rural India? Discuss. (200 words) 12.5

ग्राम उदय से भारत उदय योजना गाँवों के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना होगी।

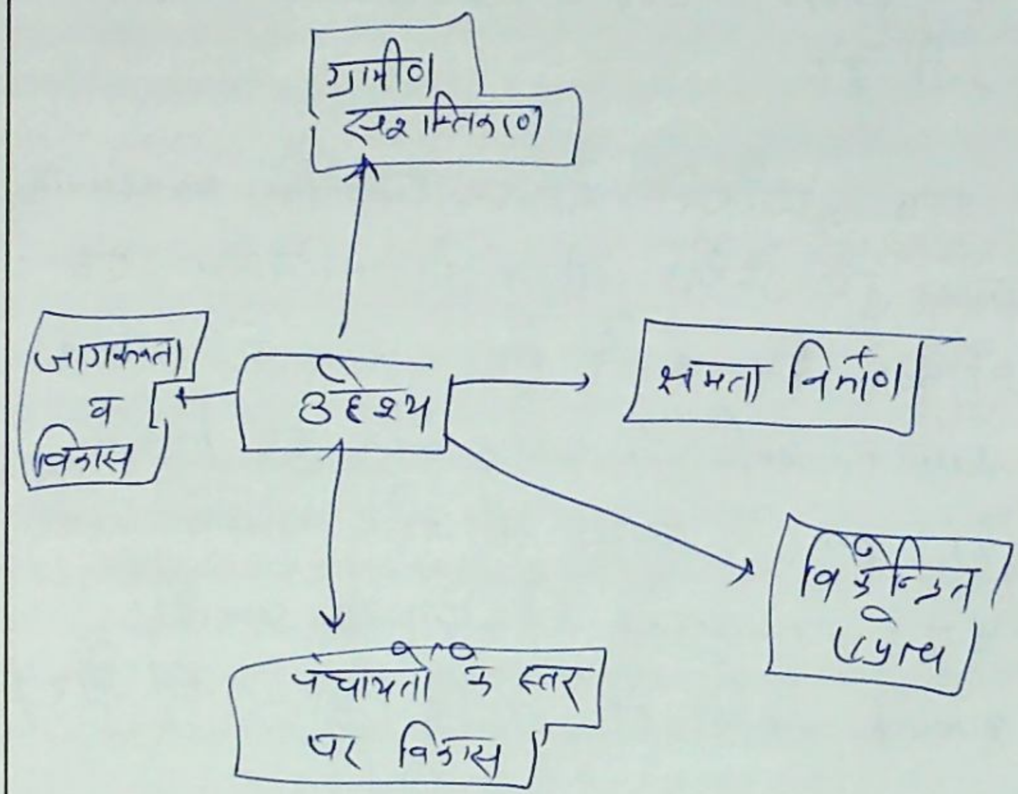

यह अभियान पंचायतों के स्तर पर गाँवों में जागरूकता प्रशिक्षणों, क्षमता निर्माण के द्वारा गाँवों को विकास की मूलभूत इकाई मानकर विकास करने पर बल देता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

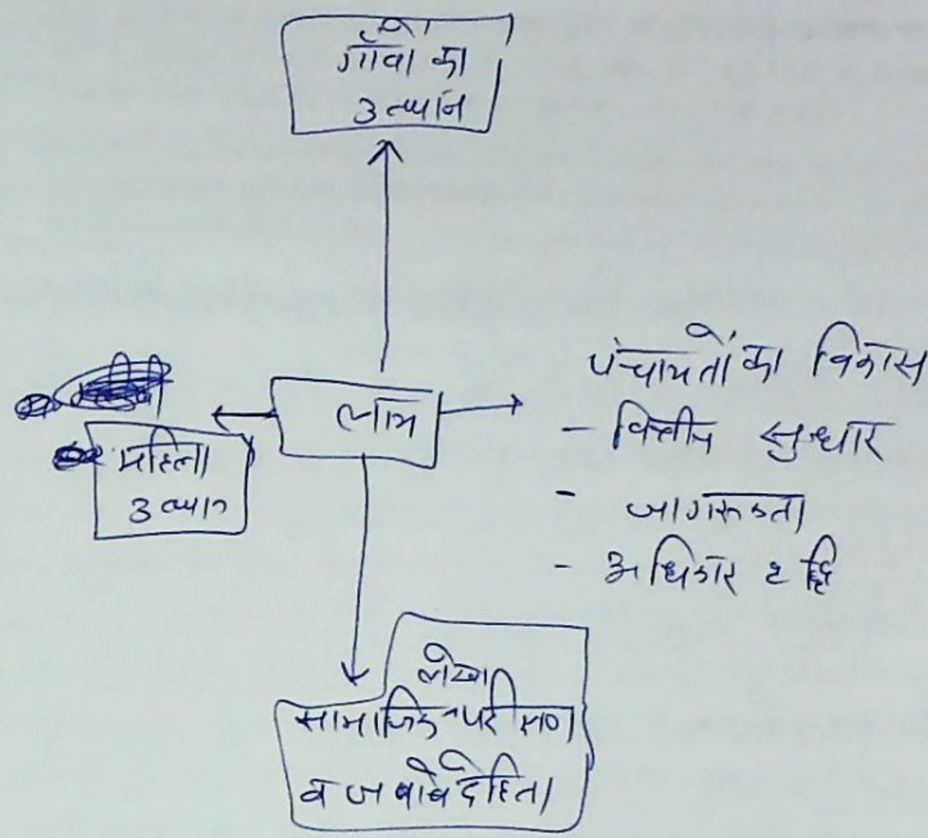

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

7. बजट 2018-19 में चर्चा में रही आयुष्मान भारत योजना के अभिलक्षणों पर प्रकाश डालें। स्वास्थ्य क्षेत्रों में उपस्थित समस्याओं के निराकरण में सहायता प्रदान करने एवं गरीबों के स्वास्थ्य के लिये मील का पत्थर साबित होने के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करें। (200 शब्द) 12.5

Highlight the features of the Ayushman Bharat Scheme unveiled in the Budget 2018-19. Evaluate it as a milestone for the health of the poor and a tool to resolve the problems of the health sector. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की योजना में बजट 2018-19 में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं -

① राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना :- इस योजना के तहत भारत के निचले 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को द्वितीयक व तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु कैशलैस बीमा की सुविधा प्रदान की जायेगी।

- सरकारी या निजी दोनों अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं।
- लाभार्थियों का पहचान सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर किया जायेगा।

मूल्यांकन

① मील का पत्थर

(क) गरीबों का 'आउट ऑफ पॉकेट' खर्च

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

कम होगा।
- द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं के भयंकर खर्चे से निजात मिलेगी।
- कैशलेस की सुविधा होने से और भी आसानी होगी व किसी भी अस्पताल में इलाज करा पायेंगे।
- स्वास्थ्य समस्या से निजात पाकर वे देश के विकास में योगदान दे पायेंगे।

चुनौतियाँ :- (क) बीमा के मॉडल की समस्या -
- श्रमजीवी जनसंख्या - अधिक
- निजी अस्पताल खर्च बढ़ाकर बता सकते हैं।

(ख) सरकार ने बजट आवंटन कम किया है।
(ग) पिछली बीमा योजना 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के परिणाम उत्साहजनक नहीं थे।

(2) हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर :- इस घटक के तहत पूरे देश में 1.5 लाख एच.डब्लू.सी. बनाये जायेंगे।
- इन केन्द्रों में सभी संचारी एवं 'गैर संचारी' रोगों का भी इलाज संभव हो सकेगा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

-गरीबों हेतु जाँच, परामर्श की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराकर, उचित मानव संसाधन व स्टाफ व्यवस्था के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।

लाभ :- (क) गरीबों की सामान्य बीमारियों का इलाज संभव

(ख) गैर-संचारी रोगों के इलाज पर बल जो आज भारत में मुख्य समस्या बनकर उभरे हैं।

चुनौतियाँ :- (क) वित्तीय पक्ष

(ख) मानव संसाधन पक्ष - इन केन्द्रों के लिये लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी।

अतः इन सभी चुनौतियों पर उचित समाधान करने, उचित क्रियान्वयन, सक्षम प्रशासन एवं उचित बीमा मॉडल अपनाकर निश्चित रूप से यह योजना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में क्रान्ति लाकर गरीबों के उत्थान में मदद कर सकती है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

8. ऊर्जा गंगा परियोजना के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालते हुए इससे होने वाले लाभों का उल्लेख करें। (200 शब्द) 12.5

Highlight the key features of the Urja Ganga Project and list the benefits associated with it. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

गंगाऊर्जा परियोजना मुख्यतः प्राकृतिक गैस ग्रिड से देश को जोड़ने की परियोजना का घटक है। इस योजना में असम के प्राकृतिक गैस के कुओं को पाइपलाइन के द्वारा उत्तरप्रदेश, प.बंगाल, झारखण्ड बिहार व उड़ीसा को विजयपुर-जगदीशपुर हजीरा लाइन 5500 किमी. के द्वारा जोड़कर ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है।

→ पिछड़े क्षेत्रों में गैस उपलब्धता बढ़ाना

→ भारतीय गैस ग्रिड का प्रमुख घटक

→ गरीबों को मुफ्त सप्लाई देने हेतु ग्रिड का निर्माण आवश्यक

— उड़ीसा, झारखण्ड के संयंत्रों तक भी ~~[illegible]~~ गैस पहुँचाना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

लाभ
- ऊर्जा सुरक्षा
- रोजगार व गरीबी उन्मूलन में सहायक
- पर्यावरण अनुकूल गैस
- अवसंरचना विकास
- पिछड़े ब्लॉक तक ऊर्जा सुविधा
- स्वास्थ्य
- वायु प्रदूषण में कमी में सहायक

- उद्योगों के विकास हेतु जैसे झारखण्ड, उड़ीसा के इस्पात संयंत्रों में भी गैस सप्लाई होने से उत्पादन वृद्धि।
- असम के कुंओं की भी मांग वृद्धि होने से पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास संभव।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

10. 'भारत की चुनावी व्यवस्था में 'एक उम्मीदवार-एक सीट' का फॉर्मूला अपनाना लोकतांत्रिक सशक्तीकरण का महत्त्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकता है।' कथन का परीक्षण कीजिये। (200 शब्द) 12.5

'Adopting the scheme of 'One Candidate-One Seat' in election system of India will strengthen democracy.' Examine. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

~~हाल ही में नीति आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अनेक बयानों में [illegible]~~

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13 (7) के अनुसार एक उम्मीदवार चाहे वह लोकसभा या ~~राज्यसभा~~ विधानसभा का हो, दो सीटों पर चुनाव लड़ सकता है।

वस्तुतः इस व्यवस्था में 2 से अधिक सीटों का प्रावधान था परन्तु बाद में संशोधन कर इसे दो सीटों तक सीमित कर दिया। परन्तु हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा इसे '1 उम्मीदवार : एक सीट' तक सीमित करने का अनुरोध किया है जिसके कारण निम्न है-

(क) मूलतः यह व्यवस्था लोकतांत्रिक चुनाव राजनीति के विरुद्ध है क्योंकि लोकतंत्र में चुनावों में एक सीट के लिये जहाँ एक ही

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

उम्मीदवार का चुनाव होता है तो एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने का औचित्य नहीं बनता है।

(ख) अन्य देशों में भी जैसे ब्रिटेन में एक सीट हेतु एक ही उम्मीदवार की व्यवस्था है

(ग) यह व्यवस्था जहाँ एक और उप-चुनावों में होने वाले धन और समय के अपव्यय का कारण है वहीं मतदाताओं की मूलभावनाओं पर कुठाराघात भी है।

इस व्यवस्था को समाप्त करने के लाभ

(क) धन व समय की बचत होगी
(ख) मतदाताओं की भावना के अनुरूप
(ग) पार्टीवादी राजनीति पर अंकुश लगेगा क्योंकि देखने में आया है कि सीट छोड़ने पर दूसरा प्रतिनिधि उसी दल का ही विजयी होता है

अन्य सुझाव :

(क) चुनाव आयोग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दो सीटों पर चुनाव लड़ता है

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

तो उसे जमानत राशि (लोकसभा हेतु 10 लाख व विधानसभा हेतु 5 लाख) जमा करानी होगी ताकि उपचुनावों में इस राशि का उपयोग किया जा सके।

(ख) विधि आयोग भी इस व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव दे चुका है

अतः चुनावो के सुधारों व लोकतांत्रिक सशक्तिकरण में इस व्यवस्था के समाप्ती एक प्रभावी कदम साबित होगी।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

11. मानव तस्करी व्यक्ति के मानवाधिकार के हनन के साथ ही मानवता के क्षीण होने का प्रतीक भी है। भारत में संवैधानिक और वैधानिक स्तरों पर मानव तस्करी की रोकथाम के लिये किये गए प्रावधानों को इंगित करें और देश के प्रथम मानव तस्करी विधेयक, 2018 के औचित्य की परीक्षा करें। (200 शब्द) 12.5

Human trafficking violates the human rights and signals degeneration of humanity. Highlight the constitutional and legal provisions in India for prevention of human trafficking. Also examine the rationale of the Human Trafficking Bill, 2018. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

दक्षिण एशियाई क्षेत्र मानव-तस्करी का 'हॉट-स्पॉट' माना जाता है। हथियारों व मादक पदार्थों के बाद मानवों की तस्करी अवैध व्यापार में तीसरे स्तर पर आता है।

भारत में मानव तस्करी को रोकने के लिये पहले के प्रयास प्रभावी नहीं रहे। ~~~~ नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों के साथ तस्करी के नेटवर्क सक्रिय हैं-

संवैधानिक प्रावधान :-

(क) अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समानता की बात करता है।

(ख) अनुच्छेद -23 - मानव दुर्व्यापार का निषेध करता है। इस अनुच्छेद में मानवों व उनके अंगों की वस्तुओं के समान खरीद - फरोख्त को निषेध करने

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

हेतु कानून बनाने का प्रावधान किया गया है।

हालिया मानव तस्करी विधेयक 2018 :- मानव तस्करी को रोकने, पीड़ितों को उचित न्याय व मुआवजा दिलवाने के लिये एक क्रान्तिकारी कदम के रूप में एवं दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के नेतृत्व कर्ता के रूप में भूमिका को बढ़ाने हेतु इस बिल का विशेष महत्व है-

प्रमुख प्रावधान :

(क) सभी गैर-पंजीकृत एजेंसियाँ जो नियोजन हेतु नेपाल आदि से कामगारों को लाती है, अवैध घोषित करना।

(ख) बिना पंजीकरण के जुर्माने व दंड की व्यवस्था।

(ग) महिलाओं को वैश्यावृत्ति आदि में जाने से रोकने के उपाय करना।

(घ) फास्टट्रैक कोर्ट की व्यवस्था।

(ङ) पीड़ितों को क्षतिपूर्ति व जुर्माने की व्यवस्था चाहे न्यायालय का फैसला आया

(च) यौन परिपक्वता की दवाईयाँ देने पर रोक।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

हो या न हो।
(च) पुरानी व्यवस्था में पीड़ित को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। अब उन्हें उचित पुनर्वास की सुविधा देना।

औचित्य लाभ

(क) मानव तस्करी जैसे वीभत्स अपराधों को रोकने व हर साल लगभग 10000 मानवों की तस्करी जैसे भयानक आँकड़ों की संख्या कम करने में उपयोगी।
(ख) विभिन्न हमारे पड़ोसी देश भी भारत को नेतृत्वकर्त्ता की भूमिका के रूप में देख रहे थे।
(ग) भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुरूप
(घ) इन पर लगाम लगाने से वैश्यावृत्ति, भिखारी बनाना, अंगों की बिक्री पर भी रोक लग सकेगी।

अतः यह विधेयक एक क्रान्तिकारी कदम है जो मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में देखी जाने वाली मानव तस्करी जैसी समस्या को रोकने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

13. चुनावों में राज्य वित्तीयन भारतीय राजनैतिक व्यवस्था को बेहतर कार्य निष्पादन के लिये प्रेरित कर सकता है। चुनावों में राज्य वित्तीयन के औचित्य को स्पष्ट करते हुए इस व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण लाभों की चर्चा करें। (200 शब्द) 12.5

State Funding of Elections can help improve the Indian political system. Explain the significance of State Funding of Elections and illustrate its benefits. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this spac

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के उपरांत से ही एक महत्वपूर्ण चुनावी सुधार के रूप में 'राज्य वित्तीयन' का मुद्दा उठता रहा है। यह एक व्यवस्था है जिसमें चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का संपूर्ण चुनाव खर्च राज्य के द्वारा वहन किया जाता है।

कारण व औचित्य :-

(क) लोकतांत्रिक समानता पर बल - वस्तुत: गरीब उम्मीदवार अपने कम खर्च करने के कारण अमीर प्रत्याशी के सामने टिक नहीं पाता है। राज्य वित्तीयन इस संदर्भ में समानता स्थापित करेगा।

(ख) सत्ता व विपक्ष में समानता :- चाहे सत्ता-पक्ष हो या विपक्ष दोनों के चुनावी खर्च में अंतर को समाप्त करने में भूमिका।

(ग) चुनावों में बढ़ता भ्रष्टाचार, अतिव्यय व काला-धन खपाने की समस्या।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

(घ) चुनावी - औद्योगिक गठजोड़ की समस्या

(ङ) पार्टीराज पर अंकुश लगेगा।

इन्द्रजीत गुप्ता समीति (चुनावी सुधार) ने भी इस व्यवस्था को चुनाव सुधारों के प्रमुख कदम मानते हुए स्टेट फंडिंग की सिफारिश की।

लाभ :-

(क) चुनावी खर्च पर अंकुश लगेगा।

(ख) सभी उम्मीदवारों में समानता स्थापित होगी जिससे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

(ग) काले -धन के खपाने की समस्या से निजात मिलेगी।

(घ) चुनावी भ्रष्टाचार, 'नोट से वोट' जैसी संकल्पनाओं पर अंकुश लगेगा।

(ङ) धन प्रयोग सीमित रहने से मतदाता भी लालच में न आकर विवेकपूर्ण चुनाव करेंगे।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

चुनौतियाँ :- (क) चुनाव आयोग के पास प्रभावी मिशनरी नहीं क्योंकि यह भी संभव है कि उम्मीदवार राज्य से वित्त लेकर भी खर्च करना जारी रखे।
(ख) चुनाव आयोग भी पक्ष में नहीं
(ग) पार्टियों के व्यय आदि की लेखापरीक्षा करवाने की जरूरत है।
(घ) राज्य के पास संसाधनों की कमी है (राजकोषीय दबाव)
(ङ) विभिन्न दलों में सहमति नहीं।

अतः व्यापक विचार-विमर्श कर ही इस व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। इससे पहले भी अन्य सुधारों जैसे दलों में पारदर्शिता बढ़ाना, चुनाव आयोग की नियंत्रक शक्तियों में वृद्धि करना आवश्यक है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

14. भारत जैसे लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में 'नागरिक घोषणा-पत्र' एक उत्तम साधन बन सकता है। इस संदर्भ में किये गए प्रयासों की एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिये। (200 शब्द) 12.5

'Citizen Charter' can become a perfect tool to ensure transparency and accountability in a democracy like India. Highlight the steps taken in this regard. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

नागरिक घोषणा पत्र नागरिकों व प्रशासन के मध्य औपचारिक समझौता है जो एक ओर प्रशासन को उसके कर्तव्यों की याद दिलाता है तो दूसरी ओर नागरिकों को उनके अधिकारों की। इस घोषणा पत्र में प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाएँ, लक्षित समूह, समयबद्धता, शिकायतों के समाधान की जानकारी उपलब्ध रहती है।

लाभ :-
(क) प्रशासनिक जवाबदेहिता में वृद्धि
(ख) नागरिक अधिकारों व जागरूकता में वृद्धि
(ग) सेवा आपूर्ति तंत्र में सुधार
(घ) अति गोपनीयता की संस्कृति से पारदर्शिता की संस्कृति में रूपान्तरण
(ङ) प्रशासन पर जनता के नियंत्रण में वृद्धि।

हालिया प्रयास

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(क) अनेक राज्यों में जैसे - राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि में नागरिक घोषणापत्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष बैंगलुरु में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई।

(ख) <u>नागरिकों का घोषणापत्र विधेयक 2011</u> को भी मंत्रिमंडल की सहमति प्राप्त हो गई है। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान हैं-

- आवश्यक सेवाओं की सूची
- समयबद्धता
- सेवा न देने पर 250 रुपये जुर्माना
- समस्त सरकारी संस्थान व सरकार से जुड़े कंपनियाँ आदि भी शामिल

(ग) इस संदर्भ में <u>'सेवोत्तम'</u> मॉडल का उपयोग किया जाना।

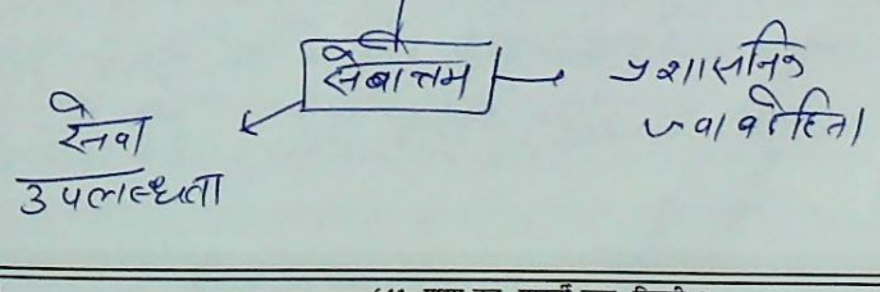

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

अन्य स्तरों पर विभिन्न सिविल समाजों एवं एन.जी.ओ द्वारा भी सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि सरकार इस व्यापक सुधार के प्रति अग्रगामी हो सके।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

15. केंद्र सरकार द्वारा विगत दिनों शुरू किये गए 'एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम' के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या यह पहल बेहतर शासन और सहकारी संघवाद को और मजबूत कर सकता है? चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

What do you know about the 'Aspirational Districts Programme' launched by the Central Government? Can this initiative strengthen good governance and cooperative federalism? Discuss. (200 words) 12.5

हाल ही में नीति आयोग द्वारा 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत केन्द्र राज्य सहभागिता को बढ़ाकर विभिन्न पिछड़े मानकों (स्वास्थ्य, शिक्षा, उपचार प्रभाव, शौचालय) के आधार पर देशभर से 115 जिलों का चयन किया गया है। केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर इन जिलों के उन्नयन का प्रयास किया जायेगा।

जहाँ तक बेहतर शासन एवं सहकारी संघवाद की मजबूती का सवाल है इन जिलों के क्रियान्वयन हेतु एक 'प्रभारी अधिकारी' की नियुक्ति का प्रावधान है यह अधिकारी 'संयुक्त सचिव' के स्तर का होगा जो एक ओर तो केन्द्रीय सहायता को तथा दूसरी ओर राज्य स्तरीय प्रयासों व

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

योजनाओं के जिले में क्रियान्वयन का कार्य देखकर संपर्क में वृद्धि करेगा।

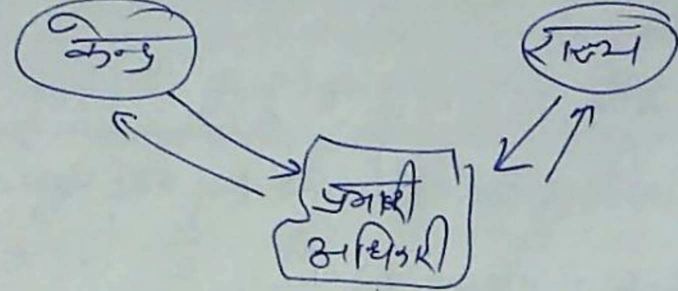

दूसरे स्तर पर देखें तो नीति-आयोग द्वारा इस योजना का पूर्ण खाका तैयार किया गया है। चूँकि नीति-आयोग भारतीय शासन में सहकारी संघवाद के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। अतः सहकारी संघवाद योजना में भी परिलक्षित होगा।

तीसरा स्तर क्रियान्वयन के स्तर पर है। योजना के निर्माण में सूचना प्रौद्यो० एवं विभिन्न डाटा का प्रयोग किया गया है वहीं क्रियान्वयन में भी राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है 'विकेन्द्रीकृत एप्रोच' के द्वारा केन्द्र की भूमिका केवल

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

सुविधा प्रदाता की होगी। फंड का आवंटन भी केन्द्र राज्य के मध्य विभिन्न अनुपातों में (60:40, 90:10) किया गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त कार्यक्रम जहाँ एक ओर पिछड़े जिलों के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं प्रशासनिक समन्वय, बेहतर प्रौद्योगिकी एवं सहकारी संघवाद का अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

16. राष्ट्रमंडल मंच पर भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक मज़बूत हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में यह मंच भारत के लिये कितना हितकर होगा? चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

India's stature at the Commonwealth has strengthened. To what extent this forum can be favourable for India? Discuss. (200 words) 12.5

हाल ही में लंदन में हुई राष्ट्रमंडल की बैठक में भारत की भूमिका में हुई वृद्धि का पता चलता है। 1947 के भारत में और वर्तमान भारत में बहुत अधिक अंतर है अतः यह स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी परिलक्षित होती है।

राष्ट्रमंडल के साथ भारत के निम्न हित हैं

① अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना कद बढ़ाने के लिये ब्रिटेन के साथ संबंध महत्वपूर्ण है। चूंकि भारत-ब्रिटेन व्यापार (लगभग 13 बिलियन $) भी अधिक है साथ ही आजादी के पश्चात. ब्रिटेन का निवेश भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है

<u>अन्य</u> - सुरक्षा परिषद. की स्थाई सदस्यता में
- भारत में शैक्षिक, वैज्ञानिक सहयोग (न्यूटन भाभा फंड) के रूप में

② चूंकि ~~सभी~~ इस संघ के सदस्यों में अनेक अफ्रीकी व द० पू० एशियाई देशों के साथ-

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

साथ प्रशान्त क्षेत्र के अनेक छोटे राष्ट्र सदस्य हैं अतः भारत निम्न तरीकों से लाभ उठा सकता है-

(क) भारतीय डायस्पोरा से लाभ लेकर - फिजी, त्रिनिनाड, इंग्लैण्ड आदि में

(ख) अफ्रीकी संबंधों को मजबूत बनाने में (एशिया- अफ्रीका आर्थिक गलियारा)

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ व विश्व व्यापार मंचों में मोल-भाव क्षमता बढ़ाने हेतु इन राष्ट्रों का सहयोग आवश्यक है।

③ भारत की नवीन-आर्थिक नीति के अनुरूप भारत में निवेश बढ़ाने (मेक इन इंडिया) हेतु

④ चूँकि ये सभी ब्रिटेन के पूर्व उपनिवेश हैं अतः भारत समान ऐतिहासिक विरासत का वर्णन कर अपनी सॉफ्ट-पावर के माध्यम से विश्व-पटल पर निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर सकता है।

⑤ ब्रेग्जिट के बाद इस संघ की भूमिका

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

में भारत का योगदान और भी बढ़ गया है।

अत: उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को इस संघ के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लाभ हो सकता है। इसके सदस्यों में भारत के पड़ोसी देश, द०पू० एशियाई देश, पश्चिम एशिया के देशों के कारण यह संघ भारत की 'एक्ट ईस्ट', 'पड़ोसी पहले', लुक वेस्ट जैसी नीतियों से साम्य रखता है।

साथ ही, बढ़ते चीन प्रभाव में हिन्द महासागर व अन्य क्षेत्रों में इन राष्ट्रों का सहयोग भी भारत के लिये आवश्यक होगा। हालिया मानवीय संकट इसका उदाहरण है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

17. क्वाड (QUAD) में भागीदारी भारत को अपने ही प्रतिस्पर्द्धी पड़ोसी के विरुद्ध एक मज़बूत आधार प्रदान कर सकता है। लेकिन इस संदर्भ में भारत को सावधानी बरतनी भी आवश्यक है। कथन की पुष्टि कीजिये। (200 शब्द) 12.5

The QUAD can provide India a strong backing against its hostile neighbor, but India needs to be equally cautious. Substantiate. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

2007 में जापानी प्रधानमंत्री द्वारा दी गई संकल्पना के अनुसार 'क्वैड' का निर्माण हुआ है यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, शांति सहयोग हेतु एक चतुर्भुज है जिसमें चार देश - भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया शामिल है।

चीन के संबंध में क्वैड की भूमिका

① हालिया डोकलाम-विवाद एवं अन्य सीमाई ~~धमकि~~ धमकियों के बाद भारत के सहयोगियों की जरूरत है और क्वैड इस रिक्तता को भर सकता है।

② जहाँ चीन अपनी ओबोर नीति, 'मोतियों की माला' के तहत भारत के घेराव का प्रयत्न कर रहा है, भारत को भी चाहिये कि जापान, अमेरिकी सहयोग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र से द० पू० एशियाई कनेक्टिविटी, उत्तर दक्षिण गलियारा आदि को विकसित कर

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

चीन पर दबाव बनाया जाये।

(3) जहाँ मालाबार अभ्यास के माध्यम से तीनों देश पहले ही रक्षा सहयोगी बन रहे हैं वहीं अन्य स्तरों पर सहयोग बढ़ाकर चीनी प्रभाव प्रतिसंतुलित किया जा सकता है।

(4) जापान - चीन विवाद, हालिया ऑस्ट्रेलिया में चीनी विरोध (शॉर्प पावर पॉलिसी), ट्रम्प का चीन-विरोधी रवैया भारत के लिये अवसर उपलब्ध कराता है।

सावधानियों की जरूरत

(क) चीन का इन तीनों देशों के साथ व्यापार अत्यन्त अधिक है। अमेरिका के साथ तो 650 बिलियन $ से अधिक का व्यापार है अतः भारत के लिये राहें आसान नहीं होंगी।

(ख) ट्रम्प का अनिश्चित रवैया - जहाँ एक ओर चीनी विरोध वहीं दूसरी ओर ओबेर नीति की प्रशंसा

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(ग) चीन निवेश भी जापान ऑस्ट्रेलिया में अधिक हैं वहीं जापानी कंपनियों का चीन में निवेश भारत की तुलना में 4 गुणा अधिक है।

(घ) अधिक प्रतिक्रिया चीन को उत्तेजित कर सकती है जिससे संबंध और अधिक खराब कर सकते हैं।

अतः भारत को चाहिये कि क्वैड को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ, चीन के साथ संबंधों को भी री-सैट किया जाये, सीमा विवादों पर वार्ता आगे बढ़ाकर, व्यापार के मुद्दों पर बातचीत जारी रखनी चाहिये क्योंकि चीनी पक्ष भी भारत के हितों के लिये महत्वपूर्ण है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

18. भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में इसे स्वहित का ध्यान भी रखना होगा। कथन का परीक्षण कीजिये। (200 शब्द) 12.5

India's commitment towards Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) should ideally be balanced with its self-interest. Examine. (200 words) 12.5

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी एक मुक्त व्यापार समझौता है जो आसियान व अन्य 6 देशों (ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, द. कोरिया, चीन, भारत) के मध्य होगा। 2013 से इस हेतु चर्चाएँ जारी हैं। भारत के सन्दर्भ में इस समझौते के निहितार्थ निम्न हैं-

सकारात्मक पक्ष

(क) व्यापार को बढ़ावा मिलेगा एवं वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

(ख) भारतीय फार्मास्युटिकल, आई.टी. उद्योग के लिये बाजारों में वृद्धि होगी।

(ग) नई तकनीकों, व्यवस्थाओं का आदान-प्रदान संभव होगा।

(घ) भारतीय निर्यातों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

परंतु इन सभी लाभों के साथ भारत के पक्ष

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

में निम्न चिंताएं विद्यमान है-

① चीनी पक्ष - चीन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत पहले से ही व्यापार घाटे में चल रहा है। अतः मुक्त व्यापार की स्थिति में इस घाटे में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। जहाँ चीन अपना बाजार भारतीय दवा, मांस, आई टी. उत्पादों हेतु खोलने को तैयार नहीं

② ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड दवाब बना रहे कि कि भारत अपना बाजार डेयरी व मांस उत्पादों हेतु खोले जोकि भारत के घरेलू उत्पादकों के हित में नहीं है

③ भारत के 'मेक इन इंडिया' अभियान पर भी सस्ती वस्तुओं के आगमन के कारण असर पड़ सकता है।

④ भारत के पुराने एफ.टी.ए. समझौतों (जापान, द० कोरिया) का अनुभव सकारात्मक नहीं रहा है।

⑤ एक अनुमान के अनुसार भारत की

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

पर आय में भी कमी होगी क्योंकि मुक्त व्यापार की स्थिति में करों दरें कम करनी होंगी।

(5) भारत के आंतरिक उद्योगपतियों व किसानों का विरोध।

अतः उपर्युक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत को फूंक-फूंककर कदम रखने की जरूरत है क्योंकि बढ़ते चीनी प्रभाव व अन्य कारकों के कारण यह समझौता भारतीय हितों के प्रतिकूल भी हो सकता है। अतः अपने हितों के अनुरूप समझौता वार्ताएं जारी रखनी चाहिए।

Copyright – Drishti The Vision Foundat

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

19. हाल के समय में देखा गया है कि भारत ने विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक और सामरिक संबंध प्रगाढ़ करने के साथ सांस्कृतिक संबंध को भी अग्रिम पंक्ति में रखा है। इस विचार को केंद्र में रखकर भारत की बदलती विदेश नीति पर एक टिप्पणी लिखिये। (200 शब्द) 12.5

While deepening the trade and strategic ties with other countries India is also keeping the cultural dimension at the forefront. In this context, comment on the evolving foreign policy of India. (200 words) 12.5

हाल के वर्षों के कई उदाहरण जैसे अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ हो, या आयुर्वेद का प्रचार भारत ने विदेश नीति में सांस्कृतिक घटकों का प्रयोग अधिकता में करना शुरू किया है। इस सन्दर्भ में भारतीय विदेश नीति के निम्न रुझान दिखलाई पड़ते हैं।

① भारत की विविधता :- अनेक क्षेत्र, धर्म, रंग, रीति-रिवाजों का देश होने के कारण भारत ने पहचाना है कि भारतीय विविधता विदेशी संबंध में योगदान दे सकती है। चाहे भारतीय डायस्पोरा का उद्बोधन हो या, धर्म के स्तर पर 'बुद्धिस्ट कूटनीति।'

② चूंकि भारत का ध्यान 'सॉफ्ट पावर मैक्सिमस' के निर्माण पर है अतः इस संबंध में सांस्कृतिक संबंधों की भूमिका अपरिहार्य है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

③ भारतीय विदेश नीति के नये उपादानों में भी चाहे वह 'एक्ट ईस्ट' हो, चाहे 'लुक वेस्ट' हो या 'नेबर फर्स्ट' हो।

इन सभी देशों के साथ भारत के प्राचीन काल से ही व्यापारिक, राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं तो क्यों न इन संबंधों का राष्ट्रीय हितों में इस्तेमाल किया जाये। उदाहरण के लिये प्रोजेक्ट मौसम, कॉटन रूट आदि इसी परिप्रेक्ष्य से संबंधित है।

④ 'पैरा डिप्लोमैसी' पर ध्यान देना भी इसी संदर्भ का उदाहरण है क्योंकि भिन्न-भिन्न राज्यों के संबंध अलग अलग देशों से जुड़ते हैं जैसे - बंगाल का बांग्लादेश से, केरल का प० एशिया से, पंजाब का कनाडा, इंग्लैण्ड से आदि। हालिया स्पाइस रूट की योजना में केरल राज्य की भागीदारी इसका उदाहरण है

Copyright – Drishti The Vision Foundat

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(5) प्रधानमंत्री की हालिया यात्राओं में भी यही बात झलकती है। प्रधानमंत्री का श्रीलंका के अनुराधापुरम में भाषण हो या अमेरीका, ऑस्ट्रेलिया में डायस्पोरा को भाषण या यू.एन. में योग के प्रति बयान, इसी सांस्कृतिक प्रसार की पुष्टि करते हैं।

इस प्रकार बदलते समय में 'सॉफ्ट पावर' के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सांस्कृतिक संबंधों का प्रयोग कर भारत ने राष्ट्रीय हित साधने का अद्भुत प्रयास किया है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

20. आने वाले वर्षों में चीन की बढ़ती हठधर्मिता भारत की विदेश नीति के लिये बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में, भारत को अपने पड़ोसी के साथ कूटनीतिक संपर्क के अतिरिक्त जनसंपर्क विस्तार पर भी ध्यान देना सही कदम होगा। चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

An assertive China poses a major challenge for India's foreign policy. While improving its diplomatic ties India should also expand the people to people engagement. Discuss. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

हालिया वर्षों में चीन के साथ सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन, चीन की भारत को घेरने की नीतियाँ (मोतियों की माला, ओबोर नीति) ने भारत की विदेश नीति के सामने गहरी चुनौतियाँ पेश की है। ग्वादर बंदरगाह, जिबूती में सैन्य हवाई अड्डा, हालिया मालदीव संकट, श्रीलंका में बंदरगाह निर्माण चीनी हठधर्मिता के हालिया उदाहरण है।

भारत को क्या करना चाहिये।

(क) पड़ोसी देशों के स्तर पर 'पड़ोसी पहले' की नीति पर अमल करना चाहिये। क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों पर संबंध के द्वारा चीनी प्रभाव प्रतिसंतुलित कर सकते है।

(ख) चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक वार्ताओं के

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

जरिये सीमा विवाद हल करने का प्रयास करना चाहिये। व्यापार के मुद्दे पर भी चीन पर टैरिफ कम करने का दबाव बनाना चाहिये।

भारत के जनसंपर्क की क्या आवश्यकता क्यों?

(क) चीन की शक्ति भारत से अधिक चाहे आर्थिक हो या सैन्य

(ख) चीन का भारत के साथ व्यापार उसके कुल व्यापार का केवल २% है

(ग) चीन के अन्य देशों से संबंध अधिक प्रगाढ़ है चाहे यूरोपीय देश हो या पश्चिम एशियाई देश।

(घ) चीन अपनी कूटनीति से भारत के पड़ोसी देशों को भी अपने पक्ष में कर रहा है। (हालिया नेपाल विवाद, मालदीव संकट)

- म्यांमार में कोको द्वीप पर चीन का निगरानी राडार
- पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, CPEC कॉरिडोर

इस प्रकार इन सभी कारणों के कारण भारत को चाहिये की वह पहल कर चीन के साथ

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

संबंधों पर बात करें। यथार्थवादी कूटनीति के प्रयोग, राष्ट्रीयता की भावना को छोड़कर चीनी पक्ष से शांतिपूर्ण समाधान जनवार्ता (Track II व III) के द्वारा ही समाधान संभव है क्योंकि युद्ध में किसी भी पक्ष का फायदा नहीं है और युद्ध का मतलब अपने 5 साल के विकास पर पानी डालना है।

Feedback

Questions ....

Model Answer & Answer Structure ....

Evaluation ....

Staff ....

Copyright – Drishti The Vision Foundation

ace)

रफ कार्य के लिये स्थान

(Space for Rough Work)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

समग्र मूल्यांकन

(Overall Evaluation)

Copyright – Drishti The Vision Foundation